



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 2010/श्रावण 4, 1932

No. 186]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 2010/SHRAVANA 4, 1932

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2010

सं. 531:विधि 710/1(एम) 1— इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया ने कम्पनी सचिव विनियमावली 1982 के प्रारूप विनियमों में और आगे संशोधन करने के लिए कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 दिनांक 30 अक्टूबर 2008 में सं. 531: विधि: 710/1(एम)/1 दिनांक 30 अक्टूबर 2008 द्वारा एक अधिसूचना का प्रकाशन पृष्ठ 1 से 27 पर किया था जिसमें उक्त विनियमावली के संशोधन के कारण प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की जनता को उपलब्ध प्रतियों की तारीख से पैंतालीस दिनों की समाप्ति से पूर्व उनकी आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और इस प्रकार जनता को उक्त राजपत्र की प्रतियों की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आपत्तियों और सुझावों का आमंत्रण किया गया था;

और जनता को उक्त राजपत्र 4 नवम्बर 2008 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और परिषद ने जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर किया है;

अतः अब कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उप-धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन से एतद् द्वारा कम्पनी सचिव विनियामवली, 1981 में और आगे संशोधन किए हैं, अर्थात्;



1. (1) इन विनियमों का नाम कम्पनी सचिव (संशोधन) विनियमावली 2010 होगा।  
(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में अन्तिम रूप से प्रकाशन होने की तारीख से लागू हो जाएंगे।
2. कम्पनी सचिव विनियमावली, 1982 में—  
(i) विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
“6. फीस — (1) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) में उल्लिखित व्यक्ति के अलावा प्रत्येक व्यक्ति, जो इंस्टीट्यूट की एसोसिएट सदस्यता के लिए आवेदन करता है, उसे अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत परिषद द्वारा नियत की गई वेश फीस देनी होगी।  
(2) एसोसिएट सदस्य जो सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए (धारा 4 की उप-धारा (2) में उल्लिखित व्यक्ति के अलावा) आवेदन किए जाने पर उसे अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत परिषद द्वारा नियत की गई प्रवेश फीस देनी होगी।  
(3) वार्षिक सदस्यता फीस प्रतिवर्ष पहली अप्रैल को देय होगी।  
(4) प्रत्येक सदस्य को अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत परिषद द्वारा नियत की गई वार्षिक फीस का भुगतान करना होगा।  
परन्तु जिस किसी वर्ष में एसोसिएट सदस्य फ़ैलो सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, उस वर्ष के लिए एसोसिएट सदस्य के रूप में उसके द्वारा संदत्त वार्षिक सदस्यता फीस, यदि कोई हो और फ़ैलो सदस्य के रूप में उसके द्वारा संदेय फीस के बीच की वार्षिक सदस्यता फीस के अंतर की राशि ही देनी होगी :  
परन्तु यह भी कि किसी वर्ष में पहली अक्टूबर को या उसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा प्रवेश लेने पर पहले वर्ष के लिए वार्षिक फीस की आधी राशि का ही भुगतान करना होगा :  
यह भी कि जिस सदस्य की साठ वर्ष या इससे अधिक की आयु होगी और वह किसी लाभप्रद रोजगार पर या प्रेक्टिसरत सदस्य नहीं होगा तो उसे वार्षिक सदस्यता फीस की आधी राशि का ही भुगतान करना होगा :  
यह भी कि जिस सदस्य की सत्तर वर्ष या इससे अधिक की आयु होगी और वह किसी लाभप्रद रोजगार पर प्रेक्टिसरत सदस्य नहीं होगा तो उसे वार्षिक सदस्यता फीस की एक-चौथाई राशि का ही भुगतान करना होगा।  
(5) (क) प्रेक्टिस प्रमाणपत्र की वार्षिक फीस प्रतिवर्ष पहली अप्रैल को देय हो जाएगी।  
(ख) प्रेक्टिसरत प्रत्येक सदस्य को अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत परिषद द्वारा नियत की गई उस प्रेक्टिस प्रमाणपत्र का भुगतान करना होगा।



परन्तु यह भी कि किसी वर्ष में पहली अक्टूबर को या उसके बाद किसी सदस्य द्वारा प्रेक्टिस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पहले वर्ष के लिए वार्षिक प्रमाणपत्र फीस की आधी राशि का ही भुगतान करना होगा;

(ii) विनियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“11. प्रेक्टिस प्रमाणपत्र का रद्द किया जाना— (1) अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत जारी किया गया प्रेक्टिस प्रमाणपत्र रद्द हो जाएगा, यदि —

- (क) अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत प्रमाणपत्रधारक का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है, या
  - (ख) परिषद इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि संबंधित व्यक्ति सुनवाई का मौका देने के बाद, उस व्यक्ति का प्रमाणपत्र किसी गलत, भ्रामक या मिथ्या जानकारी के आधार पर या परिषद् की गलती या असावधानता के कारण जारी कर दिया गया था, या
  - (ग) सदस्य ने प्रेक्टिस बंद कर दी है, या
  - (घ) सदस्य ने सम्बन्धित वर्ष में 30 सितम्बर तक प्रेक्टिस प्रमाणपत्र की वार्षिक फीस का भुगतान नहीं किया है।
- (2) प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण निम्नलिखित अवधि में प्रभावी होगा—
- (क) उपविनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामलों में उस तारीख से जिसका और उस अवधि के दौरान जिसके लिए प्रमाणपत्रधारक का नाम सदस्य के रजिस्टर से हटा दिया गया था, और
  - (ख) उप-विनियम (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत आनेवाले मामले में, 1 अक्टूबर को या उसके बाद सचिव द्वारा नोटिस जारी करने की तारीख के बाद के 15वें दिन से; और
  - (ग) किसी अन्य मामले में, ऐसी तारीख से और ऐसी अवधि के लिए जिसे परिषद निश्चित करे।

(3) जब कोई प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है तब वह तारीख जिसको और वह अवधि जिसके लिए प्रमाणपत्र रद्द रहेगा, इसकी सूचना लिखित रूप से संबंधित सदस्य को, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा रजिस्टर में दर्ज पते पर भेजी जाएगी और इसे पत्रिका में भी प्रकाशित किया जाएगा।

(4) जब प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया जाता है तो उस प्रमाणपत्र के धारक को वह प्रमाणपत्र उसे रद्द किए जाने के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से या उप-विनियम (3) के अन्तर्गत पत्रिका में प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से, जो भी बाद में पड़ती हो, 15 दिन के अन्दर सचिव को वापस लौटाना होगा।”



(iii) विनियम 13 के स्थान निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“13 सदस्यता की बहाली (1) किसी सदस्य से समुचित फार्म पर आवेदन प्राप्त होने पर, जिसका नाम विघटित कम्पनी या अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत सदस्यों के रजिस्टर से फीस की अदायगी न करने के कारण हटा दिया गया है तो परिषद उसकी सदस्यता बहाल कर सकती है बशर्ते कि वह सदस्य अन्यथा उस सदस्यता पाने का पात्र हो और वह वार्षिक सदस्यता फीस का बकाया, प्रवेश फीस तथा अतिरिक्त फीस, जिसे परिषद अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत करे, उस का भुगतान कर दे।

(2) उप-विनियम (1) के अन्तर्गत पुनः बहाली उस तारीख से होगी जिस दिन से आवेदन और फीस प्राप्त हो जाती है।

परन्तु जहां बहाली का आवेदन पत्र, जो हर प्रकार से सम्पूर्ण हो, उसी वर्ष प्राप्त हो जाता है जिस वर्ष उसका नाम हटाया गया था तो परिषद चाहे तो उसका नाम उस वर्ष की बकाया सदस्यता की वार्षिक फीस, प्रवेश फीस और बहाली की अतिरिक्त फीस का भुगतान करने पर उस तारीख से बहाल कर सकती है, जिस दिन से रजिस्टर में उसका नाम हटाया गया था:

और यह भी कि सदस्य के नाम की बहाली, जिसे अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति या अपीलीय अथारिटी या हाई कोर्ट के आदेश से हटाया गया था, केवल उक्त आदेशों के अनुसार प्रभावी हो पाएगा।

(3) रजिस्टर में सदस्य के नाम की बहाली की सूचना लिखित रूप से उस सदस्य को भेजी जाएगी और इसे जर्नल में भी प्रकाशित किया जाएगा।”

(iv) विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“14. प्रेक्टिस प्रमाणपत्र की बहाली (1) अनुमोदित फार्म पर आवेदन पत्र तथा अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत परिषद द्वारा नियत तत्सम्बन्धी फीस प्राप्त होने पर परिषद उस तारीख से प्रेक्टिस प्रमाणपत्र बहाल कर सकती है, जिस दिन से सदस्य का उक्त प्रेक्टिस प्रमाणपत्र वार्षिक फीस की गैर-अदायगी के कारण रद्द किया गया था बशर्ते कि सदस्य अपना आवेदन पत्र हर प्रकार से सम्पूर्ण कर के और साथ ही उसके साथ फीस देकर सचिव के पास उसी वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्राप्त करा दे।

(2) बहाली का आवेदन स्वीकार होने पर, प्रेक्टिस प्रमाणपत्र की बहाली की सूचना सम्बन्धित व्यक्ति को लिखित रूप में दी जाएगी और इसे जर्नल में भी प्रकाशित किया जाएगा।”



(v) विनियम 15, 16, 17, 18 और 18 में शीर्षकों के बाद कोष्ठक में निम्नलिखित शब्द अन्तर्विष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(17.11.2006 से पूर्व परिषद के समक्ष पड़ी किसी परिवाद या सूचना अथवा अनुशासन समिति या हाई कोर्ट में शुरू किए गए किसी रेफ्रेंस अथवा की गई अपील की स्थिति में लागू)”

(vi) विनियम 15 के बाद निम्नलिखित विनियम अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

“15 क. निदेशक (अनुशासन), अनुशासन निदेशालय तथा अनुशासन समिति द्वारा जांच की प्रक्रिया, परिवाद या सूचना सम्बन्धी अन्वेषण की फीस और प्रक्रिया की जानकारी देंगे (ऐसे किसी परिवाद या सूचना पर लागू जो 17.11.2006 को या इसके बाद प्राप्त होगी) (1) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार, या किसी सांविधिक अधिकरण द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर परिवाद के अलावा प्रत्येक परिवाद के साथ ढाई हजार रुपये की फीस जमा की जाएगी।

(2) ऐसे प्रत्येक परिवाद या सूचना का निपटान कम्पनी सेक्रेटरी (प्रोसीजर आफ इन्वेस्टिगेशन आफ प्रोफेशनल एंड अदर मिस्कंडक्ट एंड कंडक्ट आफ केसेज, रूल्स 2007) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

(vii) 56 से 87 डब्ल्यू विनियम का विलोपन हो जाएगा;

(viii) विनियम 98 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“98 स्थायी और अन्य समितियों का गठन— धारा 17 की उप-धारा (1) में उपबंधों के अनुसरण में परिषद तीन समितियां गठित करेगी:

(क) कार्यपालक समिति

(ख) वित्त समिति

(ग) परीक्षा समिति

(2) स्थायी समितियां परिषद के नियंत्रण, निर्देशन और देखरेख में सदा काम करेगी।

(3) परिषद अन्य समितियां गठित कर सकती है जिसमें प्रशिक्षण और शैक्षिक सुविधा समिति और वृत्ति अनुसंधान और प्रकाशन समिति अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसार गठित की जाएंगी।

(4) इंस्टीट्यूट का सचिव प्रत्येक स्थायी समिति का सचिव होगा।

(5) सचिव समिति द्वारा किए गए सभी कार्यों का रिकार्ड रखेगा, चाहे ये कार्य कागज पत्रों को परिचालित करके या समिति की बैठक में हों।

2899 40/10-2



(ix) विनियम 99 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“99 कार्यपालक समिति— (1) कार्यपालक समिति निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्:—

- (क) प्रेक्टिस प्रमाणपत्रधारक अथवा गैर प्रमाणपत्रधारक सदस्यों के नाम दर्ज करना, फैंलो सदस्यों का प्रवेश, सदस्यों के नाम हटाना और उनका प्रत्यावर्तन, प्रेक्टिस प्रमाणपत्र जारी करना और रद्द करना, सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करना परिषद की जांच निष्कर्षों पर सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करना, प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव या ऐसे कम्पनी सचिवों की फर्मों को अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के आप्रेशन से छूट की मंजूरी देना तथा सदस्यों की सूची का प्रकाशन;
  - (ख) परिषद द्वारा अपनी ओर से विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए कम्पनी सचिव व्यवसाय के अलावा अन्य किसी कारोबार और वृत्ति के साथ जुड़ने के लिए प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों को अनुमति प्रदान करना।
  - (ग) विनियम 165 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना प्रदान करने में विलम्ब होने पर माफी देना।
  - (घ) सदस्यों का रजिस्टर तथा अन्य सभी सांविधिक रजिस्टर बनाना, जिनका अधिनियम एवं अन्य विनियमों में प्रावधान है।
  - (ङ.) इंस्टीट्यूट की सम्पत्ति, आस्तियों और अन्य कोषों का नियंत्रण तथा अभिरक्षा;
  - (च) परिषद् के कार्यालय का अनुरक्षण और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कर्मचारियों को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियोजित, निलम्बन या पदच्युत या पुनः नियोजित करना, जो वह ठीक समझे।
  - (छ) वित्त समिति की सिफारिश पर वार्षिक बजट को अलग-अलग शीर्षों में परिषद द्वारा पहले मंजूर किए गए प्राक्कलनों से 20 प्रतिशत अधिक तक संभावित खर्च की मंजूरी देना।
- बशर्ते जहां कार्यपालक समिति वित्त समिति की सिफारिशों को न मानती हो तो ऐसे विषयों का निर्णय परिषद द्वारा लिया जाएगा।
- (ज) अन्य कोई कार्य, जैसे समय-समय पर परिषद् सौंपती है।
  - (2) कार्यपालक समिति को सौंपे गए कामकाज पर किसी भी निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति परिषद के पास रहेगी।

(x) विनियम 101 में शीर्षक के बाद निम्नलिखित शब्द कोष्ठक में अन्तर्विष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(17.11.2006 से पूर्व परिषद के समक्ष पड़ी किसी परिवाद या सूचना अथवा अनुशासन समिति या हाईकोर्ट द्वारा शुरू किए गए किसी रेफ्रेंस अथवा की गई अपील की स्थिति में लागू)”

(xi) विनियम 101 के बाद निम्नलिखित विनियम अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—



\*101 — क : वित्त समिति :— (1) वित्त समिति निम्नलिखित क्षेत्रों से जुड़ें और प्रासांगिक गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करेगी, अर्थात् :—

- (क) परिषद की ओर से सभी प्राप्तियों और अदायगियों के सही और यथार्थ लेखों का हिसाब रखना तथा ऐसे सभी विषयों का हिसाब रखना, जिनमें से यह प्राप्तियां और अदायगियां होती हैं एवं इंस्टीट्यूट की सभी सम्पत्तियां, प्रतिभूतियों, ऋणों, निधियों और देयताओं का हिसाब रखना;
  - (ख) इंस्टीट्यूट का वार्षिक बजट बनाना और कार्यपालक समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद इसे परिषद की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करना;
  - (ग) इंस्टीट्यूट की निधियों का नियंत्रण;
  - (घ) परिषद द्वारा मंजूर गाइडलाइनों के अनुसार समय-समय पर इंस्टीट्यूट की निधियों का निवेश और इन निवेशों का सत्यापन करना;
  - (ङ) परिषद द्वारा पहले मंजूर किए गए प्राक्कलनों के आधार पर राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के व्यय के लिए इंस्टीट्यूट की निधियों का संवितरण; परन्तु कार्यपालक समिति की सिफारिश पर परिषद द्वारा पहले मंजूर किए गए प्राक्कलनों से अधिक खर्च किया जा सकता है, जहां ऐसा करना अत्यावश्यक हो जाए, परन्तु इस अधिक खर्च की जानकारी परिषद की अगली बैठक में देना आवश्यक होगा।
  - (च) वार्षिक बजट के अलग-अलग शीर्षों में परिषद द्वारा पहले से मंजूर किए गए प्राक्कलनों से 20 प्रतिशत अधिक तक के संभावित व्यय की मंजूरी के लिए कार्यपालक समिति को सिफारिश करना;
  - (छ) इंस्टीट्यूट की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर नजर रखना और इसकी वित्तीय सूचना का प्रगटीकरण;
  - (ज) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में सचिवीय, सांविधिक तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ समीक्षा करना;
  - (झ) आंतरिक लेखापरीक्षा के ढांचे सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;
  - (ञ) आंतरिक रिपोर्टों पर समीक्षा और आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा एवं सार्थक निष्कर्षों और अनुवर्ती कार्रवाई करना।
  - (ट) ऐसे किसी भी विषय पर जिसमें किसी प्रकार के कपट या अनियमितताओं अथवा खास प्रकार की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के बारे में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आंतरिक जांच में निकाले गए निष्कर्षों की समीक्षा करना और ऐसे मामलों की रिपोर्ट परिषद को देना;
  - (ठ) आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के बारे में चर्चा करना तथा सम्बन्धित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उनके 'पोस्ट-आडिट' कराने पर चर्चा करना।
2. वित्त समिति को प्रदत्त कार्यों के निष्पादन सम्बन्धी किसी भी निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति परिषद के पास रहेगी।



(xii) विनियम 104 का विलोपन हो जाएगा।

(xiii) विनियम 114 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"114. निर्वाचनों का संचालन — (1) इस अध्याय में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय परिषद द्वारा क्षेत्रीय परिषदों के निर्वाचन कराए जाएंगे और कंपनी सचिव (परिषद का निर्वाचन) नियमावली 2006 क्षेत्रीय परिषदों के निर्वाचनों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(2) कम्पनी सचिव (परिषद का निर्वाचन) नियमावली 2006 की अनुसूची 8 में निर्दिष्ट होने पर भी, जिसे क्षेत्रीय परिषद के चुनाव के उप-विनियम द्वारा लागू किया जाता है, निर्वाचन अधिकारी—

(क) मतों की गणना में किसी भी स्तर पर चुनाव में सबसे नीचे के किसी भी प्रत्याशी को वहिष्कृत नहीं करेगा—

(i) यदि वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्याशी है, जहां पर विनियम 115 के उप-विनियम (1) में एक या इससे अधिक सीटें आरक्षित हैं; और

(ii) या वह उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का एक मात्र अनवरत प्रत्याशी है या उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से उसके स्वयं समेत अनेक अनवरत प्रत्याशियों के समकक्ष है या उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की आरक्षित सीटें कम हैं;

(ख) चुनाव में अगले निम्नतम वोट पाने वाले प्रत्याशी को वहिष्कृत कर देगा और यदि उस प्रत्याशी के मामले में खण्ड (क) के उपबंध भी लागू होते हैं तो उस अगले निम्नतम वोट पाने वाले प्रत्याशी को वहिष्कृत किया जाएगा, जिस पर खण्ड (क) के उक्त उपबंध लागू नहीं होते हैं;

(ग) ऐसे प्रत्याशी या प्रत्याशियों को जिन्हें खण्ड (क) या खण्ड (9) के अन्तर्गत चुनाव में निर्वाचन अलग रखा गया उन्हें निर्वाचित घोषित करेगा और जिन सीटों को भरा जाना शेष है, उन सीटों पर गणना जारी रखी जाएगी।

3. जहां पर किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से कोई प्रत्याशी निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं होता है जो विनियम 115 के उप-विनियम के अन्तर्गत आरक्षित सीट है या जो क्षेत्रीय परिषद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों की संख्या से कम है तो यह परिषद के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह सीट या उन सीटों को भरा जाए या न भरा जाए और यदि परिषद निर्णय लेती है कि रिक्त सीट या सीटें भरी जाएं तो उन्हें वोट देने वाले सदस्यों में से, और जो क्षेत्रीय परिषद के चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, उन सदस्यों में से, परिषद की पूर्व अनुमति लेकर क्षेत्रीय परिषद सहयोजन द्वारा किया जा सकता है तथा ये सहयोजित सदस्य उस क्षेत्रीय परिषद की कार्यालय अवधि तक पदभार संभालेंगे।



4. क्षेत्रीय परिषद के चुनाव के संबंध में कोई भी परिषद खड़ा होने पर सम्बन्धित प्रत्याशी चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से तीन दिन के अन्दर उसे प्रेजीडेंट को भेज सकते हैं और उनका निर्णय ही अन्तिम माना जाएगा।”

(xiv) विनियम 115 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“115 क्षेत्रीय परिषद में प्रतिनिधित्व: (1) प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के कम से कम छह और अधिक से अधिक बारह निर्वाचन सदस्य होंगे परन्तु यह कि उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना जारी किए जाने की तारीख को प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से कम से कम एक सदस्य निर्वाचित सदस्य होगा, जिसके लिए परिषद द्वारा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से कम से कम कितने सदस्य हों, उसके बारे में निर्णय लेगा।

(2) परिषद प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बताएगी और किसी एक विनिर्दिष्ट तारीख तक सूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह तारीख भारत के राजपत्र की प्रकाशन की तारीख से कम से कम इक्कीस दिन का समय देते हुए प्रत्याशियों का नामनिर्देशन मंगाएगी। यह सूचना सदस्यों की जानकारी के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के कार्यालयों में भी लगाई जाएगी।

(3) क्षेत्रीय परिषद, जो विनियम 111 के उप-विनियम (1) और (2) के अधीन गठित की जाती है, अपने प्रथम अधिवेशन में, परिषद से कम से कम दो व्यक्तियों को वाणिज्य, व्यापार और उद्योग तथा केन्द्रीय और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहयोजित कर सकेगी, परन्तु ऐसे सहयोजित सदस्यों को क्षेत्रीय परिषद के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।”

(xv) विनियम 116 का विलोपन हो जाएगा;

(xvi) विनियम 117, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(2) किसी क्षेत्रीय परिषद के किसी निर्वाचित सदस्य को, जो किसी वृत्तिक अथवा अन्य किसी अवचार का दोषी पाया जाता है और उस पर जुर्माना लगाया जाता है, या वह क्षेत्रीय परिषद या उसकी समितियों में जब तक लिखित रूप में आवेदन नहीं करता है एवं प्रत्येक बैठक से उसके लिए मंजूरी लिए बिना, लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में समझा जाएगा उसने तीसरी बैठक की समाप्ति पर अपना पद रिक्त कर दिया है, जब तक वह लिखित रूप में अनुपस्थिति-छुट्टी के लिए आवेदन नहीं करता है और प्रत्येक बैठक के लिए उसे मंजूर नहीं मिल जाती है।”



(xvii) विनियम 118 के निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

- "118. कार्यकाल— (1) किसी क्षेत्रीय परिषद का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से सामान्यतया चार वर्ष होगा जो परिषद की पत्रिका में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- (2) क्षेत्रीय परिषद के कार्यकाल की समाप्ति पर नई क्षेत्रीय परिषद का गठन इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप गठित किया जाएगा।

(xviii) विनियम 150 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

- "150. लेखाओं का अनुरक्षण— (1) वित्त समिति का कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित के संबंध में उपयुक्त खातों को रखे या उन्हें रखवाए—
- (क) इंस्टीट्यूट द्वारा प्राप्त तथा व्यय की गई सभी राशियों और ऐसे सभी मामले जिन पर ये प्राप्तियां और व्यय होता है;
- (ख) सभी वस्तुओं के क्रय और विक्रय
- (ग) इंस्टीट्यूट की सभी सम्पत्तियों और देयताओं का हिसाब—किताब
- (घ) और कोई भी अन्य मद, जिसके बारे में परिषद विनिर्दिष्ट करती है।
- (2) परिषद के वार्षिक खातों का हिसाब प्रति वर्ष तैयार किया जाएगा। इन वार्षिक खातों में इंस्टीट्यूट का तुलनपत्र, इंस्टीट्यूट का आय और व्यय लेखा, जिसमें उस वर्ष के इंस्टीट्यूट का अधिशेष या घाटा दिखाया जाएगा और उस वर्ष की नकद—प्रवाह विवरणी।
- (3) वार्षिक खाते तैयार करते समय वित्त समिति प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के वार्षिक खातों का भी ध्यान रखेगी और उन्हें इंस्टीट्यूट के वार्षिक खातों में समेकित करेगी।"

(xix) विनियम 152 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम का प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

- "152. लेखापरीक्षक की नियुक्ति और निवृत्ति (1) परिषद लेखापरीक्षक को अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (5) के उपबन्ध के अनुसार कार्यपाल समिति की सिफारिश पर नियुक्त करेगी।
- (2) लेखापरीक्षक उस अधिवेशन के पश्चात् जिसमें वह नियुक्त किया गया था, परिषद के अगले वार्षिक अधिवेशन की समाप्ति पर निवृत्त हो जाएगा, किन्तु पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।"

(xx) विनियम 154 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

- "154. लेखापरीक्षक पद की रिक्ति— (1) लेखा परीक्षक के पद में सामान्य अनुक्रम में उसकी पदावधि की समाप्ति से पहले रिक्ति हो जाने की दशा में अथवा



किसी वार्षिक अधिवेशन में रिक्ति भरी न जाने की दशा में, उक्त रिक्ति कार्यपालक समिति द्वारा भरी जा सकेगी और कार्यपालक समिति द्वारा इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक अगले अधिवेशन की समाप्ति तक पद धारण करेगा, परन्तु पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।

परन्तु यह भी एक ऐसी रिक्ति के दौरान पहले से कार्यरत लेखापरीक्षक, यदि कोई हो, कार्य कर सकेगा।

(xxi) विनियम 154 के बाद निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“154क. बजट प्राक्कलनों से वास्तविक आय और व्यय की तुलना— (1) परिषद प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व बजट का अनुमोदन करेगी जिसमें प्रस्तावित खर्च तथा आगामी वर्ष में होने वाले प्रत्याशित राजस्व का उल्लेख रहेगा।

(2) अन्य बातों के अलावा उप-विनियम (1) में उल्लिखित बजट में पूंजी मदों और राजस्व मदों को अलग से दिखाया जाएगा।

(3) पूंजी मदों के बजट में भूमि, भवन, पूंजीगत उपस्करों, पुस्तकों और लाइब्रेरी पर खर्च होने वाली अन्य मदों के अलावा प्रस्तावित व्यय का प्रावधान भी रहेगा।

(4) राजस्व मदों के बजट में आगामी वर्ष की प्रत्याशित आय और प्रस्तावित व्यय का प्रावधान रहना चाहिए, वहीं इसके अलावा दूरवर्ती शिक्षा, परीक्षा, सदस्यों को दी जाने वाली सेवाएं, वेतन और स्थापना सम्बन्धी अन्य मदों के खर्चों का भी प्रावधान रहेगा।

(5) इस अनुमोदित बजट में प्रत्याशित परिवर्तन शामिल करने के लिए वर्ष में संशोधित किया जा सकता है।

(6) परिषद के लेखापरीक्षकों को परिषद द्वारा अनुमोदित बजट प्राक्कलों से वास्तविक आय और व्यय की भी तुलना करनी चाहिए और उनसे हट कर कोई विशेष परिवर्तन किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट परिषद को देनी चाहिए।

(xxii) विनियम 155 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“155 लेखापरीक्षित लेखाओं और परिषद की रिपोर्ट का अनुमोदन, प्रसारण और प्रकाशन— (1) परिषद प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर व्यावहारिक रूप से यथाशीघ्र लेखापरीक्षित लेखाओं को कम से कम 15 दिन पहले प्रसारित करेगी और अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (5क) के अनुसरण में इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई विशेष अधिवेशन में इन पर विचार और अनुमोदित करेगी।

(2) परिषद उस वर्ष के लिए परिषद द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षित लेखाओं और परिषद की रिपोर्ट की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाएगी और अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (ख) के अनुसरण में अगले वर्ष की 30



सितम्बर को या उससे पहले उक्त लेखाओं और रिपोर्ट की प्रति केन्द्र सरकार और इंस्टीट्यूट के अपने सदस्यों को भेजेगी।

**(xxiii) विनियम 161 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—**

“161 सदस्यों की सूची का प्रकाशन— (1) धारा 19 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रति वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार इंस्टीट्यूट की सदस्यों की सूची को मुद्रित अथवा इलेक्ट्रानिक फार्म में प्रकाशित किया जाएगा, जिसे किसी सदस्य द्वारा अनुरोध किए जाने और परिषद द्वारा तय की गई राशि की अदायगी करने पर, जो अधिक से अधिक तीन हजार रूपए तक होगी, उसे भेजा जाएगा।

(2) सदस्यों की सूची का प्रकाशन करते हुए, जैसाकि उप-धारा (1) में उल्लेख किया गया है तथा गैर-प्रेक्टिसर एसोसिएट एवं फ़ैलो सदस्यों के बीच अन्तर कर सकती है और सदस्यों की सूची में प्रत्येक सदस्य से सम्बन्धित ऐसी कोई सूचना, जिसे वह आवश्यक और उपयोगी समझती है, दे सकती है।

किन्तु सदस्यों की सूची अथवा कंपैक्ट डिस्क अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रानिक फार्म में कम्पनी रजिस्ट्रारों कारपोरेट कार्य मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशकों तथा अन्य किन्हीं संस्थाओं को, जिनके बारे में समय-समय पर परिषद निर्णय लेती है, निःशुल्क भेजी जा सकती है।

और यह भी कि यथास्थिति, प्रिंट अथवा कंपैक्ट डिस्क अथवा इलेक्ट्रानिक फार्म में सूची की प्रतियों को उप-विनियम (1) अन्तर्गत परिषद द्वारा तय की गई राशि के साथ डाक खर्च, यदि कुछ हो तो, की अदायगी करने के बाद अन्य लोगों को भी भेजी जाएगी।

**(xxiv) विनियम 168 के बाद निम्नलिखित विनियम को अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—**

“168क. अन्य वृत्तिक संस्थाएं— (1) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग I के खण्ड (2), (3) और (5) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसी का सदस्य होना आवश्यक होगा, अर्थात्:—

(क) चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अन्तर्गत स्थापित दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स आफ इण्डिया।

(ख) कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउण्टेंट्स अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अन्तर्गत स्थापित दि इंस्टीट्यूट आफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउण्टेंट्स आफ इण्डिया।

(ग) एडवोकेट अधिनियम 1961 (1961 का 25) के अन्तर्गत स्थापित बार कौंसिल आफ इण्डिया।

(घ) आर्किटेक्ट्स अधिनियम, 1972 (1972 का 20) के अन्तर्गत स्थापित दि इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ आर्किटेक्ट्स।



- (ड.) एक्चुरीज अधिनियम, 2006 (2006 का 35) के अन्तर्गत स्थापित दि इंस्टीट्यूट आफ एक्चुरीज आफ इण्डिया।
- (च) अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत ऐसी वृत्तिक संस्थाओं और इंस्टीट्यूटों की सदस्यता, जिन्हें परिषद द्वारा कम्पनी सचिवीय सम्बन्धी अर्हताओं को मान्यता प्रदान की गई है।
- (2) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग I के खण्ड (2), (3) और (5) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की अर्हता को भारत में मान्यता प्राप्त होगी, अर्थात्:-
- (क) चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स अधिनियम 1949 के अर्थ में 'चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट'।
- (ख) कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउण्टेंट्स अधिनियम, 1959 के अर्थ में 'कॉस्ट एकाउण्टेण्ट'।
- (ग) एक्चुरीज अधिनियम 2006 के अर्थ में 'एक्चुरी'।
- (घ) किसी विधि या विधि मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का 'बेचुलर इन इंजीनियरिंग'।
- (ड.) किसी विधि या विधि मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का 'बेचुलर इन टेक्नालॉजी'।
- (च) किसी विधि या विधि मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का 'बेचुलर इन आर्किटेक्चर'।
- (छ) किसी विधि या विधि मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का 'बेचुलर आफ लॉ'।
- (ज) किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से ऑल इण्डिया कौंसिल फार टेक्नीकल एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त टेक्नीकल इंस्टीट्यूशन से 'मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन'।

“168 ख. पार्टनरशिप के लिए वृत्तिक संस्था की सदस्यता— (1) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग I के लिए खण्ड (4) और (5) के अन्तर्गत पार्टनरशिप करने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित किसी वृत्तिक संस्था का सदस्य होना आवश्यक होगा, अर्थात्:-

- (क) चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अन्तर्गत स्थापित दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स आफ इण्डिया।
- (ख) कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउण्टेंट्स अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अन्तर्गत स्थापित दि इंस्टीट्यूट आफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउण्टेंट्स आफ इण्डिया।
- (ग) एडवोकेट अधिनियम 1961 (1961 का 25) के अन्तर्गत स्थापित बार कौंसिल आफ इण्डिया।



- (घ) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा विधि द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन द्वारा इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स अथवा इंजीनियरिंग।
- (ङ.) आर्किटेक्ट्स अधिनियम, 1972 (1972 का 20) के अन्तर्गत स्थापित दि इंस्टीट्यूट आफ आर्किटेक्ट्स।
- (च) एक्चुरीज अधिनियम, 2006 (2006 का 35) के अन्तर्गत स्थापित दि इंस्टीट्यूट आफ एक्चुरीज आफ इण्डिया।
- (छ) अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत भारत के बाहर की ऐसी वृत्तिक संस्थाओं या इंस्टीट्यूशनों की कम्पनी सचिव सम्बन्धी अर्हताएं जिन्हें परिषद द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।”

एन. के. जैन सचिव एवं सी ई ओ

[विज्ञापन III/4/121/10-असा.]

नोट: मूल विनियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना आईसीएसआई सं. 710/2 (1) दिनांक 16 सितम्बर 1982 को प्रकाशित किया गया और इसके बाद निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए:

- (i) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 30.03.1984
- (ii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 03.05.1984
- (iii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 30.12.1985
- (iv) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 09.09.1986
- (v) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 23.02.1987
- (vi) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 09.03.1987
- (vii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 22.08.1988
- (viii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 23.08.1988
- (ix) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (18) दिनांक 20.08.1993 और 24.11.1993
- (x) अधिसूचना सं. /710/1/एम (17) दिनांक 21.02.1995
- (xi) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (20) दिनांक 28.11.1996
- (xii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (26) दिनांक 10.08.2001
- (xiii) अधिसूचना सं. /710/1/एम (1) दिनांक 03.05.2006
- (xiv) अधिसूचना सं. /710/1/एम (1) दिनांक 26.06.2006

## THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2010

No.531:legal:710/1(M)/1.—whereas the draft regulations further to amend the Company Secretaries Regulations, 1982 were published as required by sub-section (3) of section 39 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) at pages 1 to 27 in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 30<sup>th</sup> October, 2008 under the notification of the Institute of Company Secretaries of India No. 531:legal:710/1(M)/1 dated 30<sup>th</sup> October, 2008 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty-five days of the date on which the copies of the said notification as published in the Gazette of India were made available to the public;

And whereas objections and suggestions were invited before the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the said Gazette were made available to the public;



And whereas the said Gazette was made available to the public on 4<sup>th</sup> November, 2008;

And whereas objections and suggestions received from the public have been considered by the Council;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Company Secretaries Regulations, 1982, namely :-

1. (1) These regulations may be called the Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2010.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.
2. In the Company Secretaries Regulations, 1982,-
  - (i) for regulation 6, the following regulation shall be substituted, namely:-

“6. Fees.— (1) Every person other than a person referred to in sub-section (2) of section 4 of the Act applying for Associate membership of the Institute shall pay an entrance fee as may be determined by the Council under sub-section (3) of section 4 of the Act.
  - (2) An Associate applying for admission as a Fellow [other than a person referred to in sub-section (2) of section 4] shall pay an entrance fee as may be determined by the Council under sub-section (3) of section 5 of the Act.
  - (3) The annual membership fee shall become due on the first day of April in each year.
  - (4) Every member shall pay such annual membership fee as may be determined by the Council under sub-section (4) of section 19 of the Act:

Provided that in respect of any year in which an Associate applies for admission as a Fellow he shall pay to the Institute the difference between the annual membership fee, if any, paid by him as an Associate for that year and the fee payable by him as a Fellow:

Provided further that only half the amount of the annual membership fee shall be payable for the first year by a person admitted on or after the first day of October of that year:

Provided also that a member who is of the age of sixty years or above and is not in any gainful employment or in practice shall pay half of the annual membership fee:

Provided also that a member who is of the age of seventy years or above and is not in any gainful employment or in practice shall pay one fourth of the annual membership fee.

- (5) (a) The annual fee for certificate of practice shall become due on the first day of April in each year.
- (b) Every member in practice shall pay such annual certificate of practice fee, as may be determined by the Council under sub-section (2) of section 6 of the Act:



Provided that only half the amount of the annual certificate fee shall be payable for the first year by a member for obtaining certificate of practice on or after the first day of October of that year;”

(ii) for regulation 11, the following regulation shall be substituted, namely:-

- “11 Cancellation of Certificate of Practice. — (1) A certificate of practice issued under sub-section (1) of section 6 of the Act shall be liable for cancellation, if -
- (a) the name of the holder of the certificate is removed from the Register under sub-sections (1) and (2) of section 20 of the Act; or
  - (b) the Council is satisfied, after giving an opportunity of being heard to the person concerned, that such certificate was issued on the basis of incorrect, misleading or false information provided by the applicant, or by mistake or inadvertence on the part of the Council; or
  - (c) a member has ceased to practise; or
  - (d) a member has not paid annual fee for certificate of practice till 30<sup>th</sup> day of September of the relevant year.
- (2) The cancellation of a certificate shall be effective, -
- (a) in a case falling under clause (a) of sub-regulation (1), on the date on which and during the period for which the name of the holder of the certificate was removed from the Register of members;
  - (b) in a case falling under clause (d) of sub-regulation (1), from the 15<sup>th</sup> day following the date of issue of notice by the Secretary on or after the 1<sup>st</sup> day of October; and
  - (c) in any other case from such date and for such period, as may be decided by the Council;
- (3) When a certificate is cancelled, the date from which and the period for which the certificate shall stand cancelled shall be communicated in writing by registered post to the member concerned at the address entered in the Register and may also be published in the Journal.
- (4) Where a certificate of practice is cancelled, the holder of such certificate shall surrender the certificate to the Secretary within 15 days from the date of receipt of notice of such cancellation or from the date of the notification thereof published in the Journal, whichever is later, under sub-regulation (3).”;

(iii) for regulation 13, the following regulation shall be substituted, namely:-

“13. Restoration to membership.— (1) The Council may, on an application in the appropriate form, received in this behalf from a member whose name stood removed from the Register of members of the dissolved company or under clause (c) of sub-section (1) of section 20



of the Act, for non-payment of fees may restore his name, if he is otherwise eligible to such membership, on his paying the arrears of annual membership fee, entrance fee and additional fee as may be determined by the Council under sub-section (3) of section 20 of the Act.

(2) The restoration under sub-regulation (1) shall be with effect from the date on which the application and fee are received:

Provided that where such an application for restoration, complete in all respects, is received within the same year in which the name was removed, the Council may restore the name on his paying the annual membership fee due for that year, entrance fee and the additional fee for restoration, with effect from the date on which it was removed from the Register:

Provided further that the restoration of a member's name which was removed under the orders of the Board of Discipline or the Disciplinary Committee or the Appellate Authority or the High Court shall be effected only in accordance with such orders.

(3) The restoration of a member's name to the register shall be communicated in writing to him and may also be published in the Journal.”;

(iv) for regulation 14, the following regulation shall be substituted, namely:-

“14. Restoration of certificate of practice .— (1) The Council may, on an application made in appropriate form and on payment of such fee, as may be determined by the Council under sub-section (3) of section 20 of the Act, restore the certificate of practice with effect from the date on which it was cancelled, to a member whose certificate has been cancelled due to non-payment of the annual fee for the certificate of practice and whose application, complete in all respects, together with the fee, is received by the Secretary before the expiry of the relevant year.

(2) On acceptance of the application for restoration, the restoration of certificate of practice shall be communicated in writing to the person concerned and may also be published in the Journal”;

(v) in regulations 15, 16, 17, 18 and 19, after the headings, the following words in brackets shall be inserted, namely:-

“(Applicable to a complaint or information pending before the Council or any inquiry initiated by the Disciplinary Committee or any reference or appeal made to a High Court prior to 17.11.2006.)”.

(vi) after regulation 15, the following regulation shall be inserted namely:-

“15A. Fee and procedure for investigation of a complaint or information to be followed by the Director (Discipline), Disciplinary Directorate and procedure for inquiry by the Disciplinary Committee. [Applicable to a complaint or information received on or after 17-11-2006] .— (1) Every complaint other than a complaint filed by or on behalf of the Central Government or any

289940/10-5



State Government, or any statutory authority shall be accompanied by a fee of *rupees two thousand five hundred*.

(2) Each such complaint or information shall be dealt with in accordance with the procedure specified in the Company Secretaries (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007.”;

(vii) regulations 56 to 87 W shall be omitted;

(viii) for regulation 98, the following regulation shall be substituted namely:-

“98. Constitution of Standing and other Committees .— (1) In pursuance of the provisions contained in sub-section (1) of section 17, the Council shall constitute three Standing Committees, namely :-

- (a) An Executive Committee,
- (b) A Finance Committee, and
- (c) An Examination Committee.

(2) The Standing Committees shall at all times function under the control, direction and supervision of the Council.

(3) The Council may constitute other Committees including a Training and Educational Facilities Committee and Professional Research and Publications Committee in accordance with the provisions of sub-section (2) and sub-section (6) of section 17 of the Act.

(4) The Secretary of the Institute shall be the Secretary of every Standing Committee.

(5) The Secretary shall maintain a record of all the business transacted by a Committee either by circulation of papers or at meeting of the Committee.”;

(ix) for regulation 99, the following regulation shall be substituted namely:-

“99. *Executive Committee* .— (1) The Executive Committee shall perform the following functions, namely:—

- (a) enrolment of members with or without certificate of practice, admission of fellows, removal and restoration of names of members, issue and cancellation of certificate of practice, issue of certificates of membership, prosecution of members on the findings of the Council, granting exemption to company secretary in practice or firms of such company secretaries from the operation of sub-section (1) of section 37 of the Act and publication of the list of members;
- (b) grant of permission to a company secretary in practice to engage in any business or occupation other than the profession of company secretary in accordance with, and subject to, the restrictions specified in this behalf by the Council;



- (c) condone the delay in supplying requisite information under regulation 165;
- (d) maintenance of the Register of members and all other statutory registers which are prescribed by the Act or these regulations;
- (e) control and custody of the property, assets and funds of the Institute;
- (f) maintenance of office of the Council and for this purpose the Executive Committee may employ, suspend, discharge or re-employ the necessary staff on such terms and conditions as it may deem fit;
- (g) according approval, on recommendation of Finance Committee, to the likely expenditure upto twenty percent in excess of the estimates previously sanctioned by the Council in the respective heads of the annual budget:

Provided that where the Executive Committee does not agree with the recommendation of the Finance Committee, the matter shall be decided by the Council.

- (h) any other functions which may be entrusted to it by the Council from time to time.

(2) The Council shall have the power to review any decision taken by the Executive Committee in the performance of the functions assigned to it”

- (x) in regulation 101, after the heading the following words in brackets shall be inserted namely:-

“(Applicable to the complaint or information pending before the Council or any inquiry initiated by the Disciplinary Committee or any reference or appeal made to a High Court prior to 17.11.2006).- ”.

- (xi) after regulation 101, the following regulation shall be inserted namely:-

“101A Finance Committee.— (1) The Finance Committee shall control, implement and supervise the activities related with and incidental to the following areas, namely:-

- (a) maintenance of true and correct accounts of all the receipts and payments on behalf of the Council and the matters in respect of which such receipts and payments take place and of all the property, securities, debts, funds and liabilities of the Institute;
- (b) formulation of annual budget of the Institute and presenting it to the Council for approval, after obtaining the recommendation of the Executive Committee;
- (c) control of funds of the Institute;
- (d) investment of the funds of the Institute in securities and to vary such investments from time to time subject to the guidelines approved by the Council;



- (e) disbursements from the funds of the Institute for expenditure, both revenue and capital, based on the estimates previously sanctioned by the Council;

Provided that expenditure in excess of the estimates previously sanctioned by the Council may be incurred with the recommendation of the Executive Committee, wherever considered expedient, but such excess expenditure shall be brought to the notice of the Council at its next meeting;

- (f) making recommendation to the Executive Committee for sanction of likely expenditure upto twenty percent in excess of the estimates previously sanctioned by the Council for the respective heads of the annual budget;
- (g) overseeing the Institute's financial reporting process and the disclosure of its financial information;
- (h) reviewing with the Secretariat, Statutory and Internal Auditors, the adequacy of internal control systems;
- (i) reviewing the adequacy of internal audit function, including the structure of the internal audit;
- (j) reviewing the internal reports and any discussion with the internal auditor and significant findings and follow up there on;
- (k) reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Council;
- (l) discussing with Statutory Auditors of the nature and scope of audit and hold post-audit discussions to ascertain any area of concern.

- (2) The Council shall have the power to review any decision taken by the Finance Committee in the performance of the functions delegated to it.”;

- (xii) regulation 104 shall be omitted;

- (xiii) *for regulation 114, the following regulation shall be substituted, namely:-*

“114 Conduct of elections . — (1) Except to the extent provided in this Chapter, the elections to the Regional Councils shall be held by the Council and the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 shall apply to elections to the Regional Councils *mutatis mutandis*.



(2) Notwithstanding anything contained in Schedule 8 to the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 as applied by sub-regulation (1) to elections to the Regional Council, the Returning Officer -

(a) shall not exclude from the poll a candidate lowest on the poll at any stage in the counting of votes, —

(i) if he is a candidate from a State or Union Territory which has one or more reserved seats under sub-regulation (1) of regulation 115; and

(ii) he is either the sole continuing candidate from that State or the Union Territory or the number of continuing candidates including him from that State or the Union Territory is equal to or less than the number of seats reserved for that State or the Union territory;

(b) shall exclude the next lowest candidate on the poll and if in the case of that candidate also the provisions of clause (a) are applicable such next candidate lowest on the poll in whose case the said provisions of clause (a) are not applicable;

(c) shall declare candidate or candidates not so excluded elected the poll either under clause (a) or clause (b) as elected and shall proceed with the counting for filling the seats remaining to be filled.

(3) Where there is no candidate standing for election from any State or Union Territory which has a reserved seat under sub-regulation (1) of regulation 115 or the number of candidates for election to a Regional Council is less than the number of members to be elected, the vacant seat or seats may or may not be filled up at the discretion of the Council and in case the Council decides that the vacant seat or seats be filled up, the same may be filled up by co-option by the Regional Council from amongst the members entitled to vote in and stand for election to the Regional Council in consultation with the previous approval of the Council and the members so co-opted shall hold office for the duration of office of that Regional Council.

(4) Where any dispute arises regarding any election to a Regional Council, the matter may be referred by the candidate concerned within thirty days from the date of the declaration of the result of the election, to the President and the decision shall be final.”;

(xiv) for regulation 115, the following regulation shall be substituted, namely; -

“115 Representation on the Regional Council .— (1) Each Regional Council shall have not less than six and not more than twelve elected members provided that there shall be at least one elected member from each such State or Union Territory as is having, on the date of the issue of the notice referred to in sub-regulation (2), such minimum number of members as may be decided by the Council for each election.

2899 40/10-6



- (2) The Council shall publish in the Gazette of India a notice stating the number of persons to be elected to each Regional Council and calling for nominations of candidates for election by a specified date which shall not be less than twenty one days from the date of the publication of the said notice in the Gazette of India. Such notice shall also be displayed for information of members at the offices of each Regional Council.
- (3) The Regional Council, as constituted under sub-regulations (1) and (2) of regulation 111, may, at its first meeting, co-opt not more than two persons to represent the interests of commerce, trade and industry and the Central or State Governments with the [previous] approval of the Council provided that such co-opted persons shall have no right to vote at the meetings of the Regional Council.”;
- (xv) regulation 116 shall be omitted;
- (xvi) in regulation 117, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
- “(2) An elected member of a Regional Council who has been found guilty of any professional or other misconduct and awarded penalty of fine or does not attend three consecutive meetings of the Regional Council or Committee thereof, unless he applies for leave of absence in writing and it is granted for each meeting, shall be deemed to have vacated office from the date of the order or at the conclusion of the third meeting unless he applies for leave of absence in writing and it is granted for each meeting.”;
- (xvii) for regulation 118, the following regulation shall be substituted, namely :-
- “118 Duration of Office .— (1) The duration of office of the Regional Council shall ordinarily be four years from the date of its constitution, which shall be specified by the Council by a notification in this behalf in the Journal.
- (2) On the expiry of the duration of a Regional Council, a new Regional Council shall be constituted in the manner provided in these regulations.”;
- (xviii) for regulation 150, the following regulation shall be substituted, namely:-
- “150 Maintenance of accounts .— (1) It shall be the duty of the Finance Committee to maintain or cause to be maintained proper books of accounts with respect to-
- (a) all sums of money received and expended by the Institute and the matters in respect of which the receipt and expenditure takes place;
- (b) all sales and purchases of goods;
- (c) all the assets and liabilities of the Institute;
- (d) any other items specified in this regard by the Council.



- (2) The annual accounts of the Council shall be prepared for every year. Such annual accounts shall comprise of the Balance Sheet of the Institute, Income and Expenditure Account of the Institute comprising the surplus or deficit of the Institute for that year, and cash flow statement for that year.
- (3) While preparing the annual accounts, the Finance Committee shall take into consideration the annual accounts of the respective Regional Councils and Chapters and consolidate the same with the annual accounts of the Institute.”.

(xix) for regulation 152, the following regulation shall be substituted, namely:-

“152. Appointment of auditor and his retirement .— (1) The auditor shall be appointed by the Council at the annual meeting of the Council on the recommendation of the Executive Committee as provided in sub-section (5) of section 18 of the Act.

(2) The auditor shall retire at the conclusion of the Annual Meeting of the Council next after the meeting at which he was appointed, but shall be eligible for re-appointment.”;

(xx) for regulation 154, the following regulation shall be substituted namely:-

“154. Auditor’s vacancy in office .— In the event of any vacancy occurring in the office of auditor before the expiry of his term of office in the normal course or in the event of a vacancy not being filled up at the Annual Meeting, the said vacancy may be filled by the Executive Committee and the auditor so appointed by the Executive Committee shall hold office until the conclusion of the next Annual Meeting but shall be eligible for re-appointment.”;

Provided that, during the period of such vacancy the existing auditor may, continue to act.”;

(xxi) after regulation 154, the following regulation shall be substituted, namely:-

“154A. Comparison of actual income and expenditure with budget estimates .— (1) The Council shall approve the budget prior to the commencement of each financial year indicating expenditure proposed to be incurred and anticipated revenues for the forthcoming year.

(2) The budget refers to in sub-regulation (1) apart from the other things separately record capital items and the revenue items.

(3) The budget for the capital items shall provide proposed expenditure apart from the other items on land, building, capital equipments, books and library.

(4) The budget for revenue items shall provide anticipated income and proposed expenditure for the forthcoming year in relation to, apart from the other items, in respect of distance education, examination, services to members and salary and establishment.

(5) The budget so approved may be revised during the year to incorporate the expected changes.

(6) The auditors of the Council shall also compare the actual income and expenditure with the budget estimates approved by the Council and submit a report to the Council on the material departures.”;

289946/10-7



(xxii) for regulation 155, the following regulation shall be substituted, namely:-

“155 Approval, circulation and publication of audited accounts and Council report .— (1) The Council shall as soon as may be practicable at the end of each year circulate the audited accounts to its members at least 15 days in advance and consider and approve these accounts in a special meeting convened for the purpose in pursuance of sub-section (5A) of Section 18 of the Act.

(2) The Council shall cause to be published in the Gazette of India a copy of the audited accounts and the report of the Council for that year duly approved by the Council and shall forward a copy of the said accounts and report to the Central Government and to all members of the Institute on or before 30<sup>th</sup> day of September of the year next following in pursuance of sub-section 5(B) of section 18 of the Act.”;

(xxiii) for regulation 161, the following regulation shall be substituted, namely:-

“161 Publication of List of Members .— (1) The list of members of the Institute as on the 1<sup>st</sup> day of April each year published in print or electronic form, under sub-section (3) of section 19, shall be sent to any member, on his request and on his making payment of such amount as may be determined by the Council which shall not exceed rupees three thousand.

(2) In publishing the list of members as stated in sub-regulation (1), the Council may distinguish, in such manner as it may think fit, between the Associates and Fellows in practice and between the Associates and Fellows not in practice and provide such other information pertaining to each member in the list of members as it considers necessary and useful:

Provided that a copy of the list of members or the Compact Disc or any other electronic form, as the case may be sent free of charge to Registrars of Companies, Regional Directors under the Ministry of Corporate Affairs and such other bodies as the Council may specify from time to time.

Provided further copies of the list in print or Compact Disc or in other electronic form, as the case may be, shall also be made available to others on payment of the amount as determined by the Council under sub-regulation (1), in addition to the postal charges, if any.”.

(xxiv) after regulation 168, the following regulation shall be inserted, namely:-

“168A. Other Professional bodies .— (1) For the purposes of clauses (2), (3) and (5) of Part I of the First Schedule to the Act, a person has to be member of any of the following, namely: -

- (a) The Institute of Chartered Accountants of India established under the Chartered Accountants Act, 1949 (No.38 of 1949);
- (b) The Institute of Cost and Works Accountants of India established under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (No.23 of 1959);
- (c) The Bar Council of India established under the Advocates Act, 1961 (No.25 of 1961);.



- (d) The Indian Institute of Architects established under the Architects Act, 1972(No.20 of 1972);
- (e) The Institute of Actuaries of India established under the Actuaries Act, 2006 (No.35 of 2006);
- (f) the membership of the professional bodies or institutions whose qualifications relating to Company Secretaryship are recognized by the Council under sub-section (2) of Section 38 of the Act.

(2) For the purposes of clauses (2), (3) and (5) of Part I of the First Schedule to the Act, the following shall be the persons qualified in India, namely:-

- (a) Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949;
- (b) Cost Accountant within the meaning of the Cost and Works Accountants Act, 1959;
- (c) Actuary within the meaning of the Actuaries Act, 2006;
- (d) Bachelor in Engineering from a University established by law or an institution recognized by law;
- (e) Bachelor in Technology from a University established by law or an institution recognized by law;
- (f) Bachelor in Architecture from a University established by law or an institution recognized by law;
- (g) Bachelor of Law from a University established by law or an institution recognized by law;
- (h) Master in Business Administration from Universities established by Law or Technical Institutions recognized by All India Council for Technical Education.”;

“168B. Membership of Professional body for Partnership.— (1) For the purposes of entering into partnership under clauses (4) and (5) of Part I of the First Schedule to the Act, a person shall be a member of any of the following professional bodies, namely:-

- (a) The Institute of Chartered Accountants of India established under the Chartered Accountants Act, 1949 (No.38 of 1949);
- (b) The Institute of Cost and Works Accountants of India established under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (No.23 of 1959);
- (c) Bar Council of India established under the Advocates Act, 1961 (No.25 of 1961);
- (d) The Institute of Engineers or Engineering from a University established by law or an institution recognized by law;
- (e) The Indian Institute of Architects established under the Architects Act, 1972 (No.20 of 1972);



- (f) The Institute of Actuaries of India established, under the Actuaries Act, 2006 (No. 35 of 2006);
- (g) Professional bodies or institutions outside India whose qualifications relating to Company Secretary recognized by the Council under sub-section (2) of Section 38 of the Act.”;

N.K. JAIN Secy. and Chief Executive Officer

[ADVT III/4/121/10/Exty.]

Note : The principal Regulations were published in the Gazette of India vide notification ICSI No.710/2 (1) dated 16<sup>th</sup> September, 1982 and subsequently amended vide :-

- i) Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 30.03.1984
- ii) Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 03.05.1984
- iii) Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 30.12.1985
- iv) Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 09.09.1986
- v) Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 23.02.1987
- vi) Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 09.03.1987
- vii) Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 22.08.1988
- viii) Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated 23.08.1988
- ix) Notification No. ICSI/710/2/M(18) dated 20.08.1993 and 24.11.1993
- x) Notification No. 710/1/M/(17) dated 21.02.1995
- xi) Notification No. ICSI/710/2/M(20) dated 28.11.1996
- xii) Notification No. ICSI/710/2/M(26) dated 10.08.2001
- xiii) Notification No.710/1/(M)/1 dated 03-05-2006
- xiv) Notification No.710/1/(M)/1 dated 26-06-2006